अध्याय—एक

वर्ष 1974-75 की अर्थ-व्यवस्था

भूमिका

1.1 स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1974-75 का वर्ष हर तरह से एक ऐसा वर्ष था, जब ऐसी आर्थिक कठिनाइयां आयीं जैसी कि पहले कभी नहीं आयी थीं। फिर भी, यह वर्ष एक ऐसा वर्ष था जब सरकार ने हर कदम संकल्प लेकर उठाये जिनसे संकट की स्थितियों का मुकाबला करने की हमारी लोकतांत्रिक नीति की सुदृढ़ता का पता चलता है।

1.2 युद्ध के बाद के वर्षों में से इस वर्ष की पहली छमाही में कीमतों के बढ़ने की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज रही थी। इसके कई कारण हैं। पिछले दो वर्षों से मुद्रा-पूर्ति बेहिसाब बढ़ती चली आ रही थी। ऐसा लगता है कि रबी के मौसम में अनाज का उत्पादन तथा उसकी सरकारी खरीद के असन्तोषजनक होने की वजह से वर्ष 1974 के आरम्भिक भाग में मूल्यवृद्धि की मनोवृत्ति को और भी बल मिल गया। वर्ष के आरम्भ में पेट्रोलियम की विभिन्न चीजों के साथ-साथ उर्वरकों की कीमतें भी काफी ऊंची थीं जो जनवरी, 1974 में कच्चे पेट्रोल की सूचित कीमतों के चढ़ जाने के फलस्वरूप हुआ। मुद्रास्फीति से प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण विदेशों से मंगायी जाने वाली और अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी तौर से महत्वपूर्ण अधिकांश वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ गयीं और इस कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी तत्व जो पहले ही विद्यमान थे और अधिक शक्तिशाली हो गये। जब अनाज जैसी वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें उनकी देशी कीमतों से काफी ऊँची हों तब यदि उनका आयात कर लिया भी जाय तो ऐसी स्थिति में उससे देश के अन्दर कीमतों में कोई खास कमी नहीं की जा सकती। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों से निश्चय ही स्थिति और बिगड़ गयी फिर भी यह मानना पड़ेगा कि पिछले दो वर्षों की मुद्रास्फीति के कारण मूलतः हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की कुछ कमजोरियों में निहित हैं जो मुख्यतः 1971-72 से लगातार कम होते आ रहे हमारे कृषि उत्पादन में दिखायी पड़ते हैं।

1.3 सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होती देख कर जोरदार उपाय किये। इन उपायों का उद्देश्य मुद्रा की मांग में वृद्धि को कम करना तथा वस्तुओं को अनावश्यक रूप से जमा करते रहने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करना था। वर्ष 1974-75 के नियमित बजट में तथा दूसरे वित्त अधिनियम में लाये गये कर प्रस्तावों के मिले जुले प्रभावों के कारण तथा वर्ष के दौरान दो बार डाक की दरें तथा रेल किरायों और भाड़ों को बढ़ा दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार ने 1974-75 में अतिरिक्त वित्तीय साधन के तौर पर 690 करोड़ रुपये की रकम जुटायी जो एक रिकार्ड था। आशा है कि पूरे वर्ष में इन उपायों से 935 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। राज्यों ने भी अतिरिक्त साधन जुटाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किये और उन्होंने भी 1974-75 में 358 करोड़ रुपये की रकम जुटायी। राजस्व जुटाने का यह प्रयास मूल्यांकन की हर दृष्टि से अत्यधिक प्रभावशाली प्रयास था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस प्रकार से जुटाये गये साधनों से मिलने वाले राजस्व का अधिकांश विकास-भिन्न अपरिहार्य मदों पर खर्च हो गया जिसे यद्यपि किसी तरह से अनावश्यक नहीं कहा जा सकता।

1.4 सरकार ने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्रों में पूंजी लगाने के क्रम को बनाये रखने के लिये ठोस प्रयास किये। वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त रकमें नियत की गयीं जिससे परियोजनाओं के बढ़े हुए अनिवार्य खर्च को पूरा किया जा सके। हालांकि इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता कि सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाने का क्रम उतना तेज नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। ऐसे वर्ष में जब कि नीतिकारों के मन में सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि कीमतों में स्थायित्व लाने की नीति को प्राथमिकता दी जाय, यह स्वाभाविक और लगभग उचित भी था। साधन जुटाने के लिए किये गये इन उपायों से घाटे की मात्रा तथा मुद्रा-पूर्ति के विस्तार की रफ्तार मंद पड़ गयी और साथ ही इन उपायों से आर्थिक स्थिति को पहले से ज्यादा सुदृढ़ बनाने की दिशा में अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता मिली।

1.5 अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों के पूरक के तौर पर खर्च की जा सकने वाली उपभोक्ता-आय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष उपाय किये गये। इस तरह अतिरिक्त महंगाई भत्तों के एक अंश को तथा मजदूरी और वेतन में वृद्धि किये जाने के कारण बढ़ने वाली समूची रकम को जमा रखने, निश्चित सीमाओं के बाद लाभांश घोषित करने पर प्रतिबन्ध लगाने व अधिक आय वाले वर्गों के कर-दाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से बचत कराने के लिए जो कानून बनाया गया था, वह बढ़ते हुए घरेलू खर्च को कम करने की दिशा में एक कारगर उपाय साबित हुआ। वर्ष 1974 के मंदी के मौसम से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले बैंक ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ा दिये जाने और इन क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक चयनात्मक आधार पर ऋण देने पर नियंत्रण लगाने का उद्देश्य बचत करने को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को इस बात के लिए निरुत्साहित करना था कि वे इनवेंटरी का जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखें। हो सकता है कि इन उपायों में से कुछ उपायों का छोटा मोटा अप्रत्याशित प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा हो, फिर भी, चालू वर्ष में इन उपायों का अब तक जो प्रभाव पड़ा है वह यह है कि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि की रफ्तार स्पष्ट रूप से कम हुई है। ऐसे वर्ष में, जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की शायद ही कोई सम्भावना हो मुद्रा-पूर्ति में ज्यादा तेज रफ्तार से वृद्धि होने पर मूल्यवृद्धिकारी दबाव और बढ़ जाते।

1.6 मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक मुश्त उपायों के अंग के तौर पर सरकार ने तस्करों, जमाखोरों तथा काला बाजार में माल बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाये। लगता है कि तस्करों तथा समाज विरोधी कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्रवाई करने के कारण काले धन का प्रयोग कुछ हद तक रोका जा सका है जिसका उपयोग अब तक अनावश्यक इनवेंटरी बढ़ाने के लिए किया जाता रहा था। इस तरह चलन में आने वाली मुद्रा में होने वाली वृद्धि की गति धीमी हो जाने की वजह से उन वस्तुओं की जमाखोरी होनी कम हो गयी है जिनकी कीमतों में अचानक उछाल आ जाता है। इन कार्रवाइयों से कुल मिला कर, कीमतों में स्थायित्व लाने में सहायता मिली है।

1.7 मुद्रा प्रसार की गति को कम करने के उद्देश्य से जो कई एक उपाय किये गये उनका तात्पर्य यह नहीं है कि आर्थिक नीति की समस्याओं के प्रति मुद्राशास्त्रियों के दृष्टिकोण पर हमारा अन्ध-विश्वास है। लेकिन हाल के वर्षों में मुद्रा की मात्रा में जो भारी वृद्धि हुई है उसको ध्यान में रखते हुए मुद्राशास्त्रियों के बताये गये इस इलाज पर विश्वास करना होगा कि अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय और राजस्व विषयक अनुशासन अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। साथ ही, यह स्वीकार किया गया है कि ऐसी अर्थ-व्यवस्था में, जो मुख्यतः कृषि पर आधारित हो, कीमतों का सारा ढांचा अनाज की कीमतों पर ही निर्भर करता है और इन कीमतों में स्थिरता तभी लायी जा सकती है जब मांग और पूर्ति में उचित संतुलन लाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। चूंकि थोड़ी सी अवधि में उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता था इसलिए विदेशों से काफी मात्रा में अनाज मंगाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। तदनुसार, सरकार ने 1974-75 में लगभग 50 लाख मेट्रिक टन अनाज बाहर से मंगाने का बन्दोबस्त किया। इसके अलावा, वर्ष 1974 के अन्तिम महीनों में सरकार ने कुछ वर्गों की ओर से डाले जाने वाले इस दबाव का कि अनाज की सरकारी खरीद कीमत बढ़ा दी जाय, कीमतें बढ़ने की आशंका की स्थिति पर काबू पाने के उद्देश्य से डटकर विरोध किया यद्यपि ऐसा करना अनाज का उत्पादन बढ़ाने तथा अनाज की अधिक सरकारी खरीद करने की दृष्टि से उचित नहीं था।

1.8 सितम्बर, 1974 के तीसरे सप्ताह और उसके बाद की स्थिति को देखने से पता चलता है कि कीमतों में स्थिरता लाने के लिए किये गये उपाय कारगर होने लगे हैं। खरीफ की फसल के असन्तोषजनक होने के बावजूद वर्ष 1974 की अन्तिम तिमाही से कीमतों में कमी आयी उससे मुद्रास्फीतिकारी शक्तियों के प्रभाव के कुछ-कुछ क्षीण होने का पता चलता है। अगली रबी की फसल अच्छी होने की संभावना से भी कीमतें कुछ और उतर सकती हैं। इसके बावजूद यह मानना पड़ेगा कि रोजाना इस्तेमाल की चीजों की मांग और सप्लाई के बीच अभी काफी बड़ी खाई बनी हुई है। इसलिए इस समय यह अनुमान लगाना बुद्धिमानी नहीं होगी कि मुद्रास्फीति के विरुद्ध शुरू किया गया संघर्ष सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

1.9 आगे आने वाले पैराग्राफों में वर्ष 1974-75 की अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

सारणी 1.1

अर्थ-व्यवस्था—कुछ संकेत

	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
			(पहले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में परिवर्तन)			
1	2	3	4	5	6	7
1. स्थिर कीमतों (1960-61) के आधार पर राष्ट्रीय आय	5.7	4.9	1.4*	−0.9*	3.1**	1.0+
2. खेती की पैदावार	6.7	7.3	−0.4	−7.1*	9.1*	—
3. अनाज का उत्पादन	5.8	9.0	−3.0	−7.7*	6.8*	—
4. औद्योगिक उत्पादन	7.4	3.0	3.3	5.3	0.5	3.8†
5. उत्पादित बिजली	14.4	8.4	8.8	4.8	1.6	7.8‡
6. थोक भाव	3.7	5.5	4.0	9.9	22.6	27.2††
7. मुद्रा-पूर्ति	10.8	11.2	13.1	15.9	15.3	3.1@
8. आयात	−17.1	3.3	11.6	−1.5	56.4	53.8‡
9. निर्यात	4.1	8.6	4.8	21.9	25.9	36.2‡
10. रेलों द्वारा ढोया गया माल (निवल टन किलोमीटर)	2.5	−0.7	4.6	2.5	−10.4	3.7‡

+अनुमानित

*अनन्तिम

**जल्दी से लगाया गया अनुमान

†अप्रैल-जुलाई 1973 की तुलना में अप्रैल-जुलाई 1974

††अप्रैल-दिसम्बर 1973 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 1974

@31 मार्च, 1974 की तुलना में 31 जनवरी 1974

‡अप्रैल-नवम्बर 1973 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 1974

निवल राष्ट्रीय उत्पादन (राष्ट्रीय आय)

1960-61 की कीमतों के अनुसार

(संशोधित सीरीज)

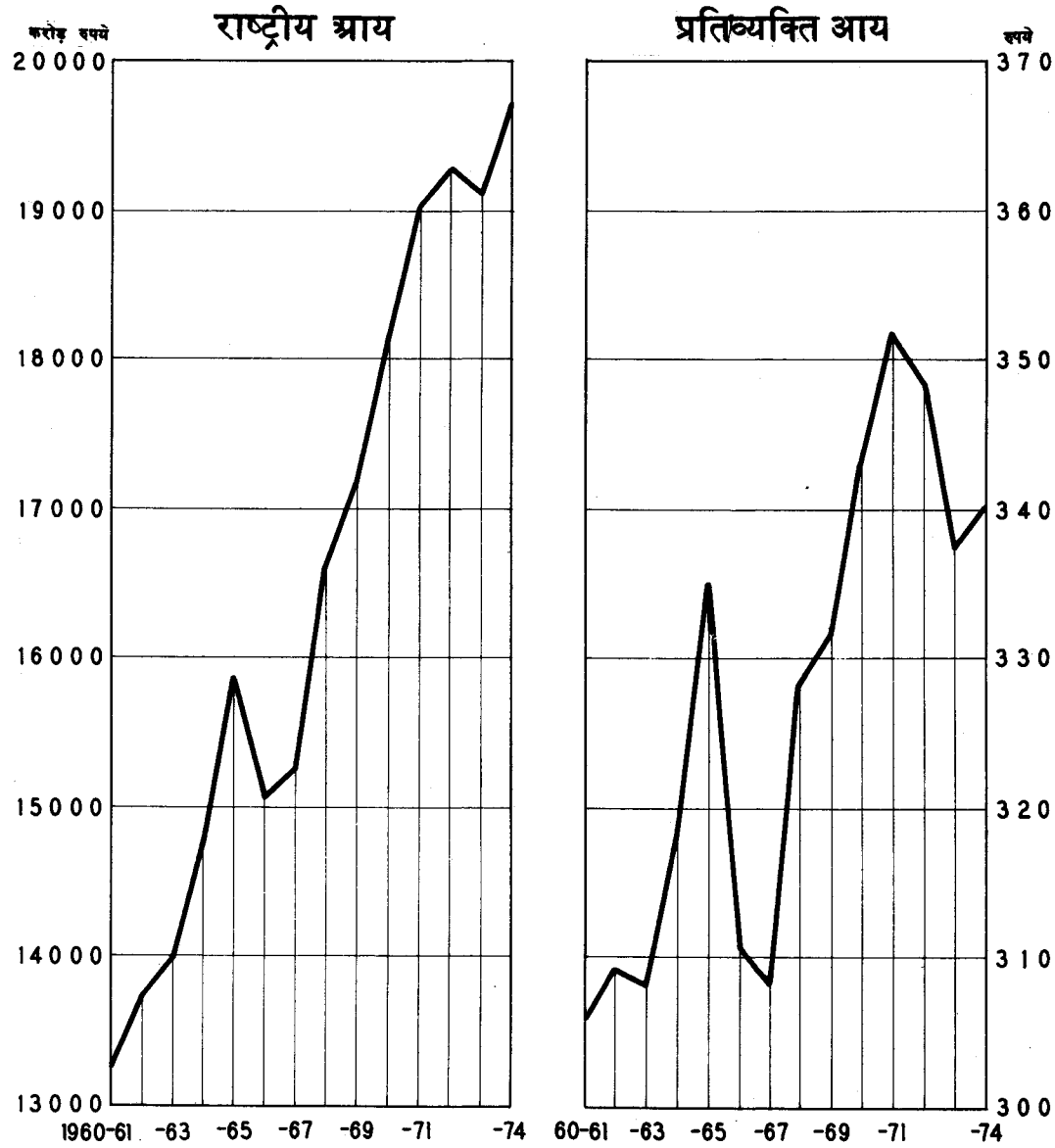

वित्त मंत्रालय, अर्थ प्रभाग

MGIPND-PLW-323/5/Fin/74-75-chart 2

राष्ट्रीय आय, बचत और लगायी गयी पूंजी

1.10 राष्ट्रीय आय के 1973-74 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि उक्त आय में केवल 3.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। चौथी आयोजना की अवधि में अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर लगभग 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उस अर्थ-व्यवस्था के लिए निराशाजनक है जहां आबादी प्रतिवर्ष 2.2 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ रही हो। चूंकि, गरीबी और अल्प विकास की बुनियादी समस्याओं को अर्थव्यवस्था में तेजी से विस्तार करके ही सुलझाया जा सकता है इसलिए हमारा निश्चित उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था में पहले की अपेक्षा ज्यादा तेज गति से वृद्धि करना होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस दिशा में 1974-75 में कोई स्पष्ट प्रगति हुई नहीं दिखायी देती क्योंकि वर्तमान अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था में एक प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है।

1.11 वर्ष 1973-74 में कितनी बचत हुई और कितनी पूंजी लगायी गयी इस बारे में सरकारी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन लगता है कि कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था में होने वाली बचत की रफ्तार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। घरेलू क्षेत्र में वास्तविक परिसम्पत्ति निर्माण के तौर पर होने वाली बचत के आंकड़ों के अभाव में इस क्षेत्र में होने वाली बचत का मोटे तौर से जो अनुमान किया गया है वह स्पष्टतः इस क्षेत्र की वित्तीय परिसम्पत्ति के आंकड़ों पर आधारित है। रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान कीमतों के आधार पर 1973-74 में वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में घरेलू क्षेत्रों में होने वाली बचत में केवल 329 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यदि इसे निवल वृद्धि के रूप में देखा जाय तो यह नगण्य बैठेगी। मौजूदा कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में, जिसमें केन्द्रीय सरकार और (स्वायत शासन सहित) राज्य सरकारें तथा उनके उपक्रम शामिल हैं, पहले के वर्ष में अपेक्षाकृत ज्यादा बचत हुई दिखायी पड़ती है लेकिन इसे यदि निवल वृद्धि के रूप में आंका जाय तो लगेगा कि उपर्युक्त बचत कीमतें बढ़ जाने के कारण घट गयी। अनुमान है कि प्राइवेट गैर-वित्तीय निगमित क्षेत्र में 1973-74 में लगभग उतनी ही बचत हुई जितनी कि 1972-73 में हुई थी। इसलिए, कुल मिलाकर 1973-74 की आन्तरिक बचत वास्तविक रूप में घट गयी लगती है।

1.12 जहां तक व्यापार में लगायी जाने वाली पूंजी का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र में 1973-74 में इस काम के लिए जुटायी जा सकने वाली पूंजी का अनुमान केन्द्रीय बजट के आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि यद्यपि मुद्रा के आंकड़ों की दृष्टि से कुछ अधिक पूंजी जुटायी गयी थी लेकिन वस्तुतः इसमें काफी कमी हुई। पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में निजी क्षेत्र में जुटायी गयी पूंजी का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। लेकिन जहां तक प्राइवेट गैर-वित्तीय निगमित क्षेत्र में पूंजी जुटाने का सम्बन्ध है, इसकी दर का स्थूल अनुमान, इस क्षेत्र को विचौलियों के माध्यम से मिलने वाली पूंजी और शेयर पूंजी और इसकी अपनी लगायी जा सकने वाली पूंजी से जो लाभ और मूल्यह्रास के लिये रखी गयी रकम से मिलती है, लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के आधार पर रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि निगमित क्षेत्र में जो कुल पूंजी जुटायी गयी उसमें 1973-74 में 9 प्रतिशत से कम की वृद्धि हुई जबकि इससे पहले के वर्ष में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.13 कुल मिलाकर, 1973-74 में राष्ट्रीय आय के अनुपात में आन्तरिक बचत और व्यापार में लगायी जाने वाली पूंजी, दोनों में, 1972-73 के मुकाबले कमी हुई लगती है। जहां आन्तरिक बचत राष्ट्रीय आय के 10 प्रतिशत की दर से हुई वहां लगायी जाने वाली पूंजी की दर राष्ट्रीय आय के लगभग 11 प्रतिशत होगी। वर्ष 1974-75 में कोई सुधार नहीं दिखायी देता है। इससे यह पता चलता है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने के लिए कितना अधिक काम करना है।

खेती

1.14 इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि भारत में खेती के क्षेत्र में जितनी प्रगति सातवीं दशाब्दी के अन्तिम वर्षों में दिखायी दी उसका क्रम बाद में टूट गया। खेती की पैदावार का सूचकांक 1973-74 में रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया अर्थात् यह 131.6 हो गया लेकिन यह 1970-71 के उच्चतम सूचकांक अर्थात् 131.4 से कुछ मामूली सा ज्यादा था। देश की आबादी के लगभग 7 प्रतिशत बढ़ने से इस बात का पता चलता है कि कृषि उत्पादन की गति धीमी हो जाने के कारण पूर्ति और मांग के बीच असन्तुलन पैदा हो गया है।

1.15 मौसम के बहुत कुछ अच्छे न रहने के कारण खेती की पैदा-वार अच्छी नहीं हुई। लेकिन यह कहना गलत होगा कि खेती की पैदावार लगातार केवल इन्हीं छोटे-मोटे कारणों से जैसे मौसम का खराब रहना, घट गयी। उदाहरण के तौर पर 1971-72 के बाद गेहूं की पैदावार कुछ इस वजह से घटी कि कल्याण सोना गेहूं को एक नया रतुआ रोग लग गया था। मौसम ज्यादा अच्छा होने के कारण आगामी रबी के मौसम में गेहूं की पैदावार फिर से बढ़ सकती है। लेकिन, गेहूं का उत्पादन लगातार तभी बढ़ाया जा सकता है जब रोग न लगने वाली नयी किस्मों के बीज लोगों के लिये उपलब्ध कराये जा सकें। जहां तक धान का सम्बन्ध है, इसके बावजूद कि चौथी आयोजना की अवधि में अधिक उपज देने वाली धान की खेती के क्षेत्र में साढ़े तीन गुनी वृद्धि हुई, इसका उत्पादन उन राज्यों में काफी नहीं बढ़ा जिन्हें धान पैदा करने वाले राज्य कहा जाता है। यद्यपि 1973-74 में धान का उत्पादन 437 लाख टन के रिकार्ड पर पहुंच गया लेकिन यह 1971-72 के अधिकतम उत्पादन अर्थात् 431 लाख मेट्रिक टन से कुछ ही ज्यादा था। अनुमान है कि 1974 की खरीफ की फसल में धान का उत्पादन 1973 की खरीफ की फसल के 407 लाख टन के मुकाबले लगभग 17 लाख टन घट गया। खासकर ऐसी स्थितियों में जबकि पानी की सप्लाई पर कोई कारगर नियंत्रण नहीं है, धान की नयी-नयी किस्मों को कीड़ों और रोगों के लगने का खतरा हमारे सामने लगातार एक विकट समस्या है। मोटे अनाजों में बाजरा को छोड़कर अधिक उपज देने वाले दूसरे अनाजों की नयी किस्में अभी लोकप्रिय नहीं हुई हैं। जहां तक दालों का सम्बन्ध है, इस समय ऐसी किस्में उपलब्ध नहीं हैं जिनसे अधिक पैदावार ली जा सके। चौथी आयोजना की अवधि में दाल का उत्पादन औसतन 109 लाख टन हुआ था और यह उत्पादन, पहली आयोजना की अवधि के औसत उत्पादन (107 लाख टन) से कुछ ही ज्यादा था। वाणिज्यिक फसलों में, नयी किस्मों का स्पष्ट प्रभाव केवल कपास पर पड़ा। लेकिन 1971-72 के बाद से इसका उत्पादन भी उस वर्ष के 66 लाख गांठों के मुकाबले कम ही रहा। कपास का उत्पादन घट कर 1972-73 में 54 लाख गांठें हो गया लेकिन 1973-74 में फिर से उत्पादन थोड़ा बढ़ गया और वह

58 लाख गांठें हो गया । अनुमान है कि 1974-75 में कपास का उत्पादन लगभग 60 लाख गांठें होगा । इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि 1974-75 में गन्ने की पैदावार लगभग उतनी ही हो जितनी 1973-74 में हुई थी । लेकिन तिलहनों और कच्चे जूट दोनों के उत्पादन के घट जाने की सम्भावना है ।

1.16 वर्तमान अनुमान के आधार पर 1974-75 में खेती की पैदावार के सूचकांक में कोई उल्लेखनीय वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है । हो सकता है कि इस वर्ष अनाज का उत्पादन, लगभग 1973-74 के 10.36 करोड़ टन के उत्पादन के बराबर ही हो । वाणिज्यिक फसलों के उप-समूह वाली फसलों का सूचकांक भी घट सकता है ।

औद्योगिक उत्पादन

1.17 वर्ष 1974 के पहले सात महीनों में औद्योगिक उत्पादन 2.3 प्रतिशत बढ़ गया । बाद के महीनों के उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए 1974 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर वर्ष 1973 के 0.7 प्रतिशत की तुलना में लगभग 2.5 प्रतिशत हो सकती है । लेकिन 1974-75 के वित्तीय वर्ष में 1973-74 के 0.5 प्रतिशत की तुलना में यह वृद्धि लगभग 3.5 प्रतिशत तक हो सकती है ।

1.18 वर्ष के शुरू के दिनों में पावर, ईंधन और परिवहन संबंधी सुविधाओं में कमी होने की वजह से औद्योगिक उत्पादन में रुकावटें आयीं । पावर पैदा करने तथा कोयले का उत्पादन करने और उसे लाने ले जाने के काम में अभी हाल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फिर भी खेती के कच्चे माल के ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना नहीं होने के कारण औद्योगिक उत्पादन की स्थिति कुल मिलाकर अनिश्चित बनी हुई है । इस बीच यदि औद्योगिक देशों में अनिश्चितता की स्थिति से हमारे निर्यात पर असर पड़ने लगा तो समस्या और भी जटिल हो जायगी ।

1.19 यह काफी संतोष की बात है कि सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम बराबर उच्च स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं । महत्वपूर्ण क्षेत्र के कई उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है । अग्रिम सूचना के अनुसार, जो खासकर अनन्तिम होती है, बिजली, इस्पात और कोयले का उत्पादन करने वाले जैसे उद्योगों के उत्पादन में अप्रैल से दिसम्बर, 1974 तक की अवधि में वर्ष 1973 की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिजली के उत्पादन में 6.0 प्रतिशत, मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन किये जाने वाले बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 10.4 प्रतिशत और कोयले के उत्पादन में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन 8.0 प्रतिशत बढ़ गया लेकिन फासफेट युक्त उर्वरकों का उत्पादन 7.1 प्रतिशत घट गया । दूसरी ओर सीमेंट और एल्यूमीनियम जैस उद्योगों का उत्पादन घट गया । सीमेंट का उत्पादन 3.5 प्रतिशत और एल्यूमिनियम का उत्पादन 17 प्रतिशत कम हो गया । उपभोक्ता वस्तुओं में वनास्पती का उत्पादन 29.3 प्रतिशत घट गया । यद्यपि सूती धागे का उत्पादन ज्यों का त्यों बना रहा लेकिन मिल के बने कपड़े का उत्पादन 3.9 प्रतिशत बढ़ा। एक ओर जहां वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों का उत्पादन 6.7 प्रतिशत घट गया वहां दूसरी ओर मोटर कारों का उत्पादन 23.7 प्रतिशत और जीपों का उत्पादन 19.7 प्रतिशत कम हो गया । स्कूटर का उत्पादन 15.0 प्रतिशत बढ़ गया । मोटर गाड़ियों के डीजल इंजनों का उत्पादन काफी ज्यादा अर्थात 45.2 प्रतिशत बढ़ गया ।

1.20 यद्यपि जुलाई, 1974 में जारी किये गये अध्यादेश से लाभांशों पर प्रतिबन्ध लगने के कारण शेयर बाजार में, खासकर नये शेयर जारी किये जाने के मामले में निराशा छा गयी फिर भी पूंजी माल समिति द्वारा स्वीकृत रकमों और सावधि ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से मांगी गयी रकमों के आंकड़ों को देखने से ऐसा स्पष्टतः जाहिर नहीं होता कि 1974-75 में उद्योगों में धीमी गति से पूंजी लगायी जा रही है । लेकिन, चूंकि पूंजी लगाने की रफ्तार निराशा और उत्साह की वृत्ति पर निर्भर करती है जिसके बारे में अनुमान करना कठिन होता है, इसलिए स्थिति पर सावधानी से नजर रखनी होगी जिससे जैसी स्थिति हो उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

कीमतें

1.21 थोक कीमतों का सूचकांक, 21 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह में उच्चतम सीमा पर पहुंच गया । यह सूचकांक, 1973 के इसी सप्ताह के सूचकांक से 32 प्रतिशत ज्यादा था । बाद के तीन महीनों में कीमतें लगभग 5 प्रतिशत गिर गयीं । इसके परिणाम-स्वरूप, कीमतों का सूचकांक दिसम्बर, 1974 के अन्त में दिसम्बर, 1973 की इसी अवधि के मुकाबले 18.8 प्रतिशत ज्यादा था । इसकी तुलना दिसम्बर, 1972 और दिसम्बर, 1973 के बीच की अवधि के सूचकांक के साथ की जानी चाहिए जिसमें 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । लेकिन अभी हाल के महीनों की इस स्वागत योग्य घटना के बावजूद वर्ष 1974 में थोक कीमतों का सूचकांक औसतन 27.3 प्रतिशत बढ़ गया जबकि 1973 में वह औसतन 19.2 प्रतिशत बढ़ा था । इससे केवल यही बात जाहिर नहीं होती कि मुद्रास्फीतिकारी तत्व हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार कितने सक्रिय रहे हैं बल्कि इस बात का भी पता चलता है कि इस मुद्रास्फीति ने हमारे आर्थिक ढांचे को कितना ज्यादा तहस नहस कर दिया है ।

1.22 यहां यह ध्यान देना होगा कि 1973-74 के दोनों वर्षों में थोक कीमतों के सूचकांक में लगभग आधी वृद्धि, खाद्य वस्तुओं की कीमतों के भारी तेजी से बढ़ जाने के कारण हुई । अगली रबी की फसल के अच्छी होने की आशा से, सरकारी अनाज वितरण व्यवस्था के जरिए सुचारू रूप से अनाज का वितरण करते रहने के लिए सरकार द्वारा विदेशों से काफी मात्रा में अनाज मंगाने से और मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि की दर के घट जाने के कारण अनुमान किया जा सकता है कि कीमतों में कुछ स्थिरता आएगी । इसके अलावा, पेट्रोलियम की चीजों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने की वजह से जो प्रभाव पड़ा था वह अब काफी हद तक कीमतों के ढांचे के साथ घुल मिल गया लगता है । इन सभी तत्वों पर विचार करने से अनुमान होता है कि अगले महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले कीमतों के बढ़ने की गति कम हो जायगी। फिर भी यदि रोजाना इस्तेमाल में आने वाली बुनियादी वस्तुओं की मांग और सप्लाई के बीच वर्तमान असन्तुलन और कृषि उत्पादन में मौजूदा अस्थिरता बनी रही तो यह कहना कठिन है कि अतिरिक्त प्रयास किये बिना कीमतों में यथोचित स्थायित्व आ जायगा ।

राजस्व तथा वित्तीय नीतियां

1.23 उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि अतिरिक्त साधन जुटाने तथा ऐसे खर्च को कम करने के लिए जो ज्यादा जरूरी नहीं है, सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयासों के बावजूद 1974-75 में बजट संबंधी घाटा बजट अनुमानों से बताये गये 126 करोड़ रुपये के घाटे से काफी ज्यादा होगा । इसका कारण यह है कि खाद्य और उर्वरक संबंधी सरकारी सहायता,

सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता और सरकारी क्षेत्र के कई उद्योगों को रोकड़ में होने वाली हानियों को पूरा करने के लिये दी जाने वाली बजट संबंधी सहायता जैसी मदों के संबंध में मूल बजट में जितने खर्च की व्यवस्था की गयी थी, उससे ज्यादा खर्च हुआ। फिर भी इस बात से थोड़ा संतोष है कि केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निवल ऋणों में वृद्धि का हिसाब लगाने पर यह पता चलता है कि चालू वर्ष में अब तक केन्द्र का जो घाटा रहा है वह पिछले साल के मुकाबले कम है। यदि केन्द्र और राज्यों, दोनों के घाटे का इकट्ठा हिसाब लगाया जाय तो यह कहना पड़ेगा कि इस दिशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को (केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को मिला कर) दिये जाने वाले निवल ऋण में चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी, 1975 तक 540 करोड़ रुपये की निवल वृद्धि हुई जबकि 1973-74 की इसी अवधि में 807 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी।

1.24 ऋण देने के मामले में ज्यादा चयनात्मक नीति अपनायी जाने के कारण चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में काफी कम वृद्धि हुई। इस तरह 31 मार्च, 1974 और 31 जनवरी, 1975 के बीच वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये बैंक-ऋण में 959 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई है वह पिछले वर्ष में हुई 1287 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले काफी कम है।

1.25 सरकार तथा वाणिज्यिक क्षेत्र दोनों को दिये जाने वाले बैंक-ऋण में थोड़ी सी वृद्धि होने और बैंकों की विदेशी मुद्रा संबंधी परिसम्पत्ति में कमी होने के संयुक्त प्रभाव के कारण चालू वर्ष में मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि की गति स्पष्ट रूप से धीमी रही है। 31 मार्च, 1974 और 31 जनवरी, 1975 के बीच मुद्रा-पूर्ति में 337 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि 1973-74 की इसी अवधि में यह रकम 960 करोड़ रुपये थी। चालू वर्ष में अब तक (31 जनवरी, 1975 तक) मुद्रा के संघटक के रूप में करेंसी में काफी कमी हुई जबकि 1973-74 की इसी अवधि में उसमें 565 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

भुगतान संतुलन

1.26 विदेशों से मंगाये जाने वाले तेल, खाद्य और उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण हमारे भुगतान संतुलन पर नये सिरे से दबाव पड़ा है हालांकि विदेशों को भेजी जाने वाली हमारी वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ जाने के कारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ज्यादा ऋण लिये जाने के कारण उक्त दबाव को अब तक काबू में रखा गया है।

1.27 सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार 1973-74 में निर्यात में 1972-73 के मुकाबले लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन दूसरी ओर विदेशों से मंगायी जाने वाली वस्तुओं की कुल कीमत में इससे भी तेज गति से अर्थात् लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप 1973-74 में हमारी विदेशी मुद्रा में 437.7 करोड़ रुपये की कमी हो गयी जबकि 1972-73 में 100.3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अधिशेष के रूप में थी। वर्ष 1974-75 के पहले आठ महीनों में निर्यात की अपेक्षा आयात की गति लगातार काफी तेज रही। निर्यात में केवल 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन आयात के मूल्य में 54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार-सन्तुलन में 425 करोड़ रुपये की कमी हो गयी।

1.28 भारत ने फरवरी, 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिपूरक वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत 62.6 करोड़ रुपये की रकम निकाली थी। भारत ने चालू वर्ष में अब तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 488 करोड़ रुपये की निकासी की है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋण आगामी 3 से लेकर 7 वर्षों की अवधि में चुकाये जाने हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक आने वाले वर्षों में आयात में कमी नहीं होती अथवा पहले की अपेक्षा भारी मात्रा में निर्यात नहीं होता तब तक हमें व्यापार सन्तुलन की असाधारण भीषण समस्या का मुकाबला करना पड़ेगा। इस संदर्भ में सबसे पहले आवश्यक यह है कि हम मंगाये जाने वाले अन्न, पेट्रोल तथा उर्वरकों पर कम से कम निर्भर रहें। हमारे व्यापार सन्तुलन की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो भी योजना बनायी जाय उसमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किये गये हैं वह अभी तक कारगर नहीं हुए हैं। अभी हाल में जो हमारा निर्यात बढ़ा उसका मुख्य कारण है—संयोगवश होने वाली विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि और विदेशों में हमारी चीजों की भारी मांग। मात्रा की दृष्टि से 1973-74 में भारत का निर्यात लगभग 3.6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा और चौथी आयोजना की अवधि में वह औसत में 4.2 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं बढ़ा था। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के गिर कर सामान्य स्तर पर आ जाने की संभावना है इसलिए अगर हम अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए नये सिरे से ठोस कदम नहीं उठाते तो हो सकता है कि जो आय निर्यात के कारण भारत को होती है, उसको धक्का लगे।

सिंहावलोकन

1.29 वर्ष 1974-75 पांचवीं आयोजना का पहला वर्ष था। जब हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के परिणामों को राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बचत और लगायी जाने वाली पूंजी की दर जैसी सामान्य कसौटियों से आंकते हैं तब दुर्भाग्य से इस वर्ष के परिणाम पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में लगाये गये अनुमानों के अनुरूप नहीं दिखायी पड़ते हैं। संभवतः इस वर्ष ऐसी स्थिति से बचा भी नहीं जा सकता था जब कि न केवल खरीफ की पैदावार के काफी घट जाने से ही नहीं बल्कि कुछ विदेशी कारणों से भी हमारी अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंच चुका था। मुद्रास्फीति के भारी दबाव को ध्यान में रखते हुए हमारी आर्थिक नीति में सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह रहा कि अर्थ व्यवस्था की स्थिति में स्थायित्व लाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाय। चूंकि तेजी से बढ़ रही कीमतों को ध्यान में रखते हुए किसी नयी विकास नीति को नहीं शुरू किया जा सकता था इसलिए यह जरूरी हो गया कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में दीर्घावधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय अल्पावधिक लक्ष्यों पर बल दिया जाता। यह सोचना भी बेवक्त की बात थी कि हमारी अर्थव्यवस्था को मूल्य स्थिरता का आधार मिल गया है। कुछ भी हो, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की जो हमारी समस्याएं हैं और जो हमारी चिन्ता का विषय बनती जा रही हैं उनका मुकाबला करने का एकमात्र उपाय यही है कि अर्थव्यवस्था में खास खास मदों में चयनात्मक आधार पर प्रोत्साहन दिया जाय जिससे बचत करने तथा पूंजी लगाने की दर में और अधिक वृद्धि की जा सके। जब तक अर्थव्यवस्था में विकास नहीं होता तब तक हमारे जैसे गरीब देश में कीमतों में भी स्थायित्व नहीं आ सकेगा। यह एक चुनौती है जिसका मुकाबला नीतिकारों को 1975-76 में करना है।